ट्रम्प का कश्मीर प्रस्ताव

लेखक -निरुपमा सुब्रमण्यन (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

27 जुलाई, 2019

"भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए अमेरिका का एक अपना अलग इतिहास रहा है। लेकिन भारत ने हमेशा ही इन प्रयासों को विफल किया है। अब इस बार डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में क्या चल रहा है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं?"

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के अमेरिकी दौरे पर जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बयान जारी कर के कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए कहा था और वह 'मदद करना चाहते भी है।'

हालांकि, ट्रम्प के इस दावे के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार और विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने पलटवार करते हुए कहा कि "यह भारत का लगातार रुख रहा है कि सभी मुद्दों पर केवल द्विपक्षीय बातचीत ही होगी और पाकिस्तान को साथ किसी भी ऐसी बातचीत के लिए सीमा पार से आतंकवाद की गतिविधियों को खत्म करना होगा, कश्मीर या किसी अन्य भारत-पाकिस्तान मुद्दे पर मध्यस्थता के लिए कोई जगह नहीं है।"

भारत ने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है। अब यह देखना है कि वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ असमान और अप्रत्याशित संबंधों पर यह बयान कैसा प्रभाव डालता है। दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया अच्छी तरह से प्रकरण को चुपचाप दफनाने और आगे बढ़ने पर हो सकती है।

भारत, पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता पर जोर क्यों देता है?

भारतीय स्थिति ऐतिहासिक रूप से अपने आंतरिक मामलों में बाहरी लोगों के प्रति अविश्वास की भावना से उपजी है, साथ ही यह अपनी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीयता की रक्षा करने की आवश्यकता पर भी जोर देता है और इसे संदेह है कि मध्यस्थों द्वारा कश्मीर को पाकिस्तान की नजरों से देखा जायेगा। इन्हीं सब कारणों से भारत कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी देश की मध्यस्था नहीं चाहता है।

जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 1947 में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी आक्रमण पर आवाज उठाई थी, को अपनी गलती का एहसास जल्द ही हो गया। संयुक्त राष्ट्र मिशन, जिसमें डिक्सन मिशन भी शामिल है, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों के विभाजन (लद्दाख से भारत, PoK और उत्तरी क्षेत्र पाकिस्तान तक, जम्मू दोनों के बीच विभाजित है) के लिए 1950 की डिक्सन योजना बनी, के साथ-साथ घाटी में एक जनमत संग्रह ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पर दरवाजा बंद करने के भारत के दृढ़ संकल्प को मजबूत किया।

भारत और पाकिस्तान के बीच समस्याओं के द्विपक्षीय समाधान के लिए रूपरेखा 1972 के शिमला समझौते में लिखी गई थी और 27 साल बाद लाहौर घोषणा में दोहराई गई थी। बहरहाल, पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे का 'अंतर्राष्ट्रीयकरण' कर के भारत के जम्मू-कश्मीर के प्रति दृष्टिकोण को उलटने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दांव जारी रखा है और भारत के कश्मीर के 'अवैध कब्जे' की आलोचना करने के लिए हर वैश्विक मंच का इस्तेमाल किया है।

जब पहले भी अमेरिका ने दखलंदाजी की

जहाँ एक तरफ भारत ज्यादातर यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि वह किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं करेगा, वहीं दूसरी तरफ ट्रम्प की पेशकश पहली बार नहीं है जहाँ किसी अमेरिकी नेता ने भारत और पाकिस्तान से कश्मीर विवाद को हल करने के लिए अपनी तरफ से मदद् की पेशकश की हो।

1993 में, रॉबिन राफेल, जिन्होंने पहले क्लिंटन प्रशासन में राज्य विभाग के नए बनाए गए दक्षिण एशिया डिवीजन का नेतृत्व किया, ने एक्सेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट को कबाड़ करने की कोशिश की और भारतीय कूटनीतिक प्रयासों के वर्षों के प्रयासों को कम आंकते हुए कहा कि अमेरिका के लिए, कश्मीर एक 'विवादित क्षेत्र' है।

उस वक्त इनके बयान को ट्रम्प की टिप्पणी से कहीं अधिक गंभीरता से लिया गया था और भारत में उन्हें पाकिस्तान समर्थक और भारत विरोधी के रूप में देखा जाने लगा था। 1995 में, राफेल ने अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति को बताया कि दक्षिण एशिया में हमारे शीर्ष विदेश नीति के लक्ष्य प्रशासन की वैश्विक प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। तनाव को कम करने और संघर्षों को शांतिपूर्वक हल करने में मदद् करने के लिए हम इस विवाद को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास करते रहेंगे।

जैसे-जैसे नई दिल्ली का उदारीकरण आर्थिक रूप से बढ़ा, राफेल का विदेश विभाग का प्रभाव फीका होता गया। क्लिंटन 2.0 ने द्विपक्षीय वार्ता पर भारतीय रुख अपनाया। लेकिन 1990 में कश्मीर और सीमापार आतंकवाद में पाकिस्तान का हाथ स्पष्ट होने के बाद यह भारत ही था, जिसने घाटी में पाकिस्तान के बढ़ते कदम पर लगाम लगाने के लिए बाहरी मदद् मांगी थी।

1999 में, भारत और पाकिस्तान के परमाणु संपन्न होने के बाद, यह अमेरिकी हस्तक्षेप था जिसने कारगिल संकट को समाप्त किया। वाजपेयी सरकार, नवाज शरीफ सरकार द्वारा की जा रही कारगिल में घुसपैठ को बंद करने के लिए क्लिंटन प्रशासन के संपर्क में थी, यहाँ तक कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेनाओं का मुकाबला भी किया था।

नवाज शरीफ 3 जुलाई को वॉशिंगटन पहुंचे, एक संघर्ष-विराम के लिए क्लिंटन की मदद मांगी, जिसमें कश्मीर पर अमेरिकी-गारंटी निपटान शामिल था। लेकिन उन्हें नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की बिना शर्त वापसी के लिए सहमत होना पड़ा। क्लिंटन ने उन्हें कश्मीर के मुद्दे पर प्रत्यक्ष रूप से मदद् करने से मना कर दिया और उस वर्ष के पहले द्विपक्षीय लाहौर घोषणा पर अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जो कश्मीर और अन्य मुद्दों को हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है।

9/11 के बाद, जिसने यूएनएससी समर्थित आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानूनी शासन की शुरुआत की, भारत ने पाकिस्तान से निपटने में मदद् के लिए दुनिया की ओर तेजी से रुख किया। लेकिन भारत के पास एक ही तरह का मुद्दा था: पाकिस्तानी सेना पर पनपने वाले आतंकवादी समूहों का अंत, पाकिस्तान सेना पर दबाव बनाने और राजनीतिक नेतृत्व को अपने क्षेत्र पर भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधि की अनुमति देने से रोकने और इस तरह के हमले होने पर उसे रोकना। यह फिर से अमेरिका ही था जिसने तनाव को कम किया और भारत को संसद पर 2001 के जैश-ए-मोहम्मद द्वारा किये गये हमले के बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध करने से रोका।

2008 में, जब बराक ओबामा व्हाइट हाउस में अपने पहले कार्यकाल के लिए एक उम्मीदवार थे, उन्होंने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सीमा के पार से तालिबान के हमलों पर एक सवाल के जवाब में कहा: कि "पाकिस्तान और भारत के साथ कश्मीर संकट को हल करने का प्रयास करना एक गंभीर मुद्दा है जो अगले प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। मुझे लगता है कि एक ऐसा क्षण है जहाँ संभवत: हम उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण है।

भारत को इस विचार का खंडन करने की जल्दी थी और ओबामा ने अपने राष्ट्रपति पद के आठ वर्षों में इस पर कभी चर्चा नहीं की।

अन्य प्रयास: यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे

यूनाइटेड किंगडम ने भी मध्यस्थ बनने में रुचि दिखाई है। कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय रुचि को आमतौर पर भारत-पाकिस्तान की व्यस्तता में एक अभिव्यक्ति मिली है, जब द्विपक्षीय मोर्चे पर 'कुछ भी नहीं' हो रहा है और विशेष रूप से कश्मीर मुद्दा भी इसी अवधि में उबाल पर है।

पिछले साल, कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् की चुभने वाली रिपोर्ट के अलावा, नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री केजेल मैग्ने बॉन्डेविक ने श्रीनगर का दौरा किया, वहाँ अलगाववादी नेतृत्व से मुलाकात की और लौटने के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का दौरा किया।

नॉर्वे की संघर्ष स्थितियों में मध्यस्थता के लंबे इतिहास ने बॉन्डेविक की यात्रा पर बहुत अटकलें लगाईं। भारतीय पक्ष में, उन्होंने बताया कि उन्हें आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने आमंत्रित किया था। भारत सरकार, जिसने स्पष्ट रूप से घाटी में यात्रा की सुविधा और सुरक्षा प्रदान की थी, ने कोई टिप्पणी नहीं की; भारत में नॉर्वे के राजदूत ने बाद में स्पष्ट किया कि यह एक व्यक्तिगत यात्रा थी।

राष्ट्रपति ट्रम्प की टिप्पणी को समझना होगा

कश्मीर में ट्रम्प की कोशिश के कई कारण हो सकते हैं या उन्हें लगता होगा की यह मुद्दा काफी सुलझा हुआ है, जिससे निपटने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस साल फरवरी में, उन्होंने भारत-पाकिस्तान गतिरोध को खत्म करने करने का दावा किया था जो पुलवामा हमले से उत्पन्न हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका ने भारतीय वायु सेना के पायलट की रिहाई में एक भूमिका निभाई थी, जिसे एलओसी के पार पकड़ा गया था।

जैश प्रमुख मसूद अजहर को 'वैश्विक आतंकवादी' के रूप में मान्यता देने के लिए चीन को मजबूर करने में भी अमेरिका ने बड़ी भूमिका निभाई है।

इसके अलावा, अभी हाल ही में, ट्रम्प ने हाफिज सईद की गिरफ्तारी का श्रेय लिया था। शायद, अमेरिकी राष्ट्रपति को लगता है कि वह समस्या को हल करने के लिए पहले से ही आधा रास्ता तय कर चुके है, तभी उन्होंने ऐसा बयान दिया था। हो सके उन्हें यह भी लग रहा हो कि अगर उनका प्रशासन अफगानिस्तान में तालिबान को वार्ता की मेज तक खींचने में सफल हो सकता है, तो वह भारत और पाकिस्तान के साथ भी ऐसा कर सकता है।

GS World टीम...

शिमला समझौता

परिचय

- 3 जुलाई, 1972 को भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है।
- इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 20 दिसंबर, 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। उन्हें विरासत में एक टूटा हुआ पाकिस्तान मिला।
- सत्ता संभालते ही भुट्टो ने यह वादा किया कि वह शीघ्र ही बांग्लादेश को फिर से पाकिस्तान में शामिल करा लेंगे। पाकिस्तानी सेना के अनेक अधिकारियों को, देश की पराजय के लिए उत्तरदायी मान कर, बर्खास्त कर दिया गया था।

पृष्ठभूमि

- कई महीने तक चलने वाली राजनीतिक-स्तर की बातचीत के बाद जून, 1972 के अंत में शिमला में भारत-पाकिस्तान शिखर बैठक हुई।
- इंदिरा गाँधी और जुल्फिकार भुट्टो ने, अपने उच्चस्तरीय मंत्रियों और अधिकारियों के साथ, उन सभी विषयों पर चर्चा की, जो 1971 के युद्ध से उत्पन्न हुए थे।
- साथ ही उन्होंने दोनों देशों के अन्य प्रश्नों पर भी बातचीत की। इनमें मुख विषय थे, युद्ध बंदियों की अदला-बदली, पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को मान्यता का प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाना, व्यापार फिर से शुरू करना और कश्मीर में नियंत्रण रेखा स्थापित करना।
- लंबी बातचीत के बाद भुट्टो इस बात के लिए सहमत हुए कि भारत-पाकिस्तान संबंधों को केवल द्विपक्षीय बातचीत से तय किया जाएगा।
- शिमला समझौते के अंत में एक समझौते पर इंदिरा गाँधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए।

समझौते के मुख्य बिंदु

- इसमें यह प्रावधान किया गया कि दोनों देश अपने संघर्ष और विवाद समाप्त करने का प्रयास करेंगे और यह वचन दिया गया कि उप-महाद्वीप में स्थाई मित्रता के लिए कार्य किया जाएगा।

सीधी बात करेंगे

- इन उद्देश्यों के लिए इंदिरा गाँधी और भुट्टो ने यह तय किया कि दोनों देश सभी विवादों और समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी बातचीत करेंगे और स्थिति में एकतरफा कार्यवाही करके कोई परिवर्तन नहीं करेंगे।
- वे एक दूसरे के विरुद्घ न तो बल प्रयोग करेंगे, न प्रादेशिक अखण्डता की अवेहलना करेंगे और न एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप करेंगे।
- दोनों ही सरकारें एक-दूसरे देश के विरुद्ध प्रचार को रोकेंगी और समाचारों को प्रोत्साहन देंगी, जिनसे संबंधों में मित्रता का

विकास हो। दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सभी संचार संबंध फिर से स्थापित किए जाएंगे।

आवागमन की सुविधाएं

- आवागमन की सुविधाएं स्थापित की जाएंगी, ताकि दोनों देशों के लोग आसानी से आ-जा सकें और घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकें।

व्यापार बढ़ाएंगे

- जहाँ तक संभव होगा, व्यापार और आर्थिक सहयोग शीघ्र ही फिर से स्थापित किए जाएंगे।

सहयोग करेंगे

- विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में आपसी आदान-प्रदान को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

नियंत्रण रेखा

- स्थाई शांति के हित में दोनों सरकारें इस बात के लिए सहमत हुई कि भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाएं अपने-अपने प्रदेशों में वापस चली जाएंगी।
- दोनों देशों ने 17 सितंबर, 1971 की युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा के रूप में मान्यता दी और यह तय हुआ कि इस समझौते के बीस दिन के अंदर सेनाएं अपनी-अपनी सीमा से पीछे चली जाएंगी।
- यह तय किया गया कि भविष्य में दोनों सरकारों के अध्यक्ष मिलते रहेंगे और इस बीच अपने संबंध सामान्य बनाने के लिए दोनों देशों के अधिकारी बातचीत करते रहेंगे।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:-
   1. भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंध के लिए 2 जुलाई,1972 को शिमला समझौता संपन्न हुआ।
   2. शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान ने तय किया था कि किसी भी विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से द्विपक्षीय बातचीत के जरिए हल किया जायेगा।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements-**
   1. Shimla Agreement was concluded on 2nd July, 1972 for bettering relation between India and Pakistan..
   2. In Shimla Agreement, India and Pakistan had decided that all disputes will be resolve through bilateral discussion.

   Which of the above statements is/are correct?
   (a) Only 1 (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2 (d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः कश्मीर विवाद के आलोक में अमेरिकी मध्यस्थता के दावों का मूल्यांकन करते हुए, यह भी बताइए कि यह भारत के लिए कितना चिंताजनक है और क्यों? तर्क सहित स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द)

Q. Evaluating the claim of American mediation with respect to Kashmir dispute, explain how worrisome it is for India and Why. Explain with reasons.

(250 Words)

नोट : 26 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।